

प्रेषक,

के०डी० भट्ट,  
प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबधक,  
मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,  
नैनीताल।

न्याय अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 27 मार्च, 2015

विषय- मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल कार्यालय हेतु सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-36/XXXVI(1) एक/2014-234/2001 दिनांक 24-02-2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान हेतु पूर्व में विभिन्न शासनादेशों के द्वारा सृजित 426 एवं शासनादेश संख्या-148/ XXXVI (1) एक/2010-234/2001 दिनांक 31 अगस्त 2010 के द्वारा सृजित बैच सेक्रेटरी ग्रेड-1 के 03 पदों (कुल 429 अस्थायी पदों) की निरन्तरता वर्तमान शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाये वर्ष 2015-16 हेतु दिनांक 01-03-2015 से 29-02-2016 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त पदों का सृजन मूलरूप में शासनादेश सं०- 234/न्याय अनुभाग/2001 दिनांक 02-05-2001, शासनादेश संख्या-22-एक (2) न्याय विभाग/ 03 दिनांक 27-08-2003, शासनादेश संख्या-8 एक (2)/न्याय विभाग/2004 दिनांक 17.01.2004, शासनादेश संख्या-25-एक (2)/न्याय विभाग/2004 दिनांक 06-08-2004, शासनादेश सं०-181/ XXXVI(1) एक/2006-234/2001 दिनांक दिनांक 13-12-2006, शासनादेश सं०- 67-एक(1) XXXVI (1) 2008 दिनांक 03-03-2008, शासनादेश सं०-230/XXXVI(1) 2009-234/2001 दिनांक 11-08-2009 एवं शासनादेश सं०-148/XXXVI(1) एक/2010-234/2001 दिनांक 31-08-2010 द्वारा किया गया था।

2- उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक के अनुदान सं०-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-102-उच्च न्यायालय-03-उच्च न्यायालय-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-1270/76-दस दिनांक 20-07-1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-877/दस-92-24(8)/92 दिनांक 07-11-1992 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किये गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किये जा रहे हैं।

4- उक्त के साथ ही वित्त(वे०आ०-सा०नि०)अनुभाग-7 के शासनादेश संख्या-118(1)/XXXVII(7)2006 दिनांक 31-08-2006 की छाया प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि उपरोक्त सृजित पदों में से 05 वर्ष पूर्ण करने वाले पदों के स्थायीकरण के संबंध में शासनादेश

कमश:-02

में उल्लिखित 09 बिन्दुओं पर बिन्दुवार आख्या सहित पदों के स्थायीकरण का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोक्त।

भवदीय

(के0डी0भट्ट)  
प्रमुख सचिव

संख्या-77(1)/XXXVI(1)/2015-563 / 2001 तददिनांक:-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
- 2- महानिबन्धक, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल।
- 4- वित्त अनुभाग-5 / कार्मिक अनुभाग / एन0आई0सी0 / गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव